# वाढवण बंदर येथे भरावा संदर्भात प्रसिद्ध पत्रक

मुंबई, २८ फेब्रुवारी २०२५: वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (व्हीपीपीएल) पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे देशातील पहिले ग्रीनफील्ड व मेगा पोर्ट विकसित करत आहे. हे बंदर १४४८ हेक्टर क्षेत्रामध्ये भराव टाकून विकसित केले जाणार आहे. हा भराव समुद्रात केला जाईल, यासाठी सुमारे २०० दशलक्ष घनमीटर वाळू समुद्रात उत्खनन करून वापरली जाईल. प्रस्तावित वाढवण बंदरापासून पासून सुमारे ६० किमी अंतरावरून व दमणच्या किनाऱ्यापासून ५० किमी अंतरावरून समुद्रातून ही वाळू आणण्यात येईल. यासाठी खाण मंत्रालयाने ऑफशोअरवरील १०२७७.१ हेक्टर (१०२.७७ चौरस किमी) क्षेत्र राखीव ठेवले आहे. आयआयटी मद्रासने प्रत्यक्ष साइटवर बोअर होल घेऊन सविस्तर अभ्यास केला असून गोळा केलेले नमुने तपासले गेले आहेत. आयआयटी मद्रासने प्रमाणित केले आहे की ही वाळू भरावासाठी अतिशय योग्य आहे. जेएनपीएने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये वाळूचे आरक्षण आणि भराव करण्यासाठी खाण मंत्रालयाकडे अर्ज केला होता. खाण मंत्रालयाने २१.१२.२०२३ रोजी अधिसूचनेद्वारे व्हीपीपीएलसाठी सदर क्षेत्र खाणकामासाठी राखीव ठेवले. आज २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी खाण मंत्रालयाने ऑफशोअर एरिया मिनरल (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन्स) अॅक्ट २००६ अंतर्गत १० वर्षांच्या कालावधीसाठी खाण परवाना जारी केला आहे. महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत खाण आणि कोळसा मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी यांनी व्हीपीपीएलचे सीएमडी आणि जेएनपीएचे अध्यक्ष श्री उन्मेष शरद वाघ, भा.रा.से. यांना हे लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआय) सुपूर्द केले. भारत सरकारचे खाण सचिव श्री कांता राव, भा.प्र.से. आणि महाराष्ट्र सरकारचे माननीय खाण मंत्री श्री शंभूराज देसाई हे देखील यावेळी उपस्थित होते.

जमिनीवर उत्खनन करून काढलेल्या २००० दशलक्ष घनमीटर वाळूची किंमत १२००० कोटी रुपये आहे ज्यामध्ये भारत सरकारला मिळणारी १४४० कोटी रुपये रॉयल्टी समाविष्ट आहे. परंतु समुद्रातून काढलेल्या वाळूमुळे जमिनीवरून काढलेल्या वाळू आणि मुरुमच्या तुलनेत ६००० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. खर्चात बचत करण्याव्यतिरिक्त, समुद्रातून काढलेल्या खाणकामाचा जमिनीवरून काढलेल्या खाणकामाच्या तुलनेत पर्यावरणावर नगण्य परिणाम होतो.

वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड **(VPPL)** बद्दल:

पालघर जिल्ह्यातील दहाणूजवळ वसलेले वाढवण बंदर हे भारताचे १३वे प्रमुख आणि सर्वात मोठे कंटेनर बंदर होणार आहे. हे बंदर लँडलॉर्ड मॉडेलअंतर्गत विकसित केले जात असून, टर्मिनल्स सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावर उभारले जात आहेत. या प्रकल्पाला १९ जून २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून, त्याची उभारणी दोन टप्प्यांत केली जाणार आहे.

प्रभावी भौगोलिक स्थान आणि देशातील प्रमुख अंतर्देशीय क्षेत्रांशी अखंड जोडणी यामुळे हे बंदर भारताच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. हे सर्व ऋतूंमध्ये कार्यरत राहील आणि त्याची खोली मोठ्या जहाजांना हाताळण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. हा प्रकल्प सागरमाला उपक्रमाचा एक भाग आहे.

वाढवण बंदर १००% हरित बंदर म्हणून विकसित होत असून, सुरुवातीपासूनच पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उपक्रमांना प्राधान्य दिले जात आहे.

मीडिया चौकशीसाठी संपर्क:
अंबिका सिंग, उपमहाव्यवस्थापक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन आणि प्रशिक्षण), वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड

**मोबाईल क्र:** +919920372677
**ई-मेल:** ambikasingh@jnport.gov.in

# गहरे मसौदे वाले ग्रीनफील्ड वाढवण बंदरगाह के लिए भराव हेतु अपतटीय भूमि निर्माण के लिए रेत खनन पर प्रेस नोट

**मुंबई, 28 फरवरी 2025:** वाढवण पत्तन परियोजना लिमिटेड पालघर जिले में गहन गहराई हरित क्षेत्र वाढवण पत्तन परियोजना को विकसित कर रहा है। यह बंदरगाह 1448 हेक्टेयर की पुनर्प्राप्त भूमि पर बनाया जाना है। पुनः प्राप्त की गई भूमि समुद्र में बनाई जाएगी, जिसमें लगभग 200 मिलियन क्यूयूएम की रेत भरी जाएगी। रेत को समुद्र में एक स्थान पर निकाला जाएगा जो स्थल (साईट) से 60 किमी और दमन के तट से 50 किमी दूर है। इस उद्देश्य के लिए खनन मंत्रालय द्वारा तट पर 10277.1 हेक्टेयर (102.77 Sq.KM) क्षेत्र को आरक्षित किया गया है। आईआईटी मद्रास द्वारा स्थल (साईट) पर वास्तविक बोर होल लेकर विस्तृत अध्ययन किया गया था और एकत्र किए गए नमूनों का परीक्षण किया गया था। आईआईटी मद्रास ने प्रमाणित किया है कि उक्त रेत सुधार उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। जनेप प्राधिकरण ने अक्टूबर 2023 में रेत के आरक्षण और सुधार के लिए खान मंत्रालय को एक आवेदन दिया था। खनन मंत्रालय ने 21 दिसंबर 2023 को वाढवण पत्तन परियोजना लिमिटेड के लिए खनन के लिए उक्त क्षेत्र आरक्षित किया। जिस की अधिसूचना आज 28 फरवरी, 2025 को खनन मंत्रालय ने जारी कर 10 वर्ष की अवधि के लिए अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 2006 के तहत खनन अनुज्ञप्ति जारी की है। खनन और कोयला मंत्री मा. श्री जी. किशन रेड्डी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मा. श्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में वाढवण पत्तन परियोजना लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और जनेप प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री उन्मेष शरद वाघ, भा.रा.से., को आशय पत्र (एलओआई) सौंपा। खनन मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री कांता राव, भा.प्र.से., और महाराष्ट्र साकार के खनन मंत्री मा. श्री शंभूराज देसाई भी उपस्थित थे।

भूमि से 2000 मिलियन क्यूयूएम रेत की लागत Rs.12000 करोड़ है जिसमें भारत सरकार को रॉयल्टी के रूप में Rs.1440 करोड़ शामिल हैं। लेकिन समुद्र की रेत ने भूमि स्रोतों से उपयोग की जाने वाली रेत और मुरम के मुकाबले Rs.6000 करोड़ की बचत की है। लागत में बचत के अलावा समुद्र से खनन का पर्यावरणीय प्रभाव भूमि पर खनन की तुलना में नगण्य है।

**वीपीपीएल के बारे में:**

महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू के निकट स्थित **वाढवण** बंदरगाह भारत का 13वां प्रमुख और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह बनने जा रहा है। इसे लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है, जहां टर्मिनलों का निर्माण सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से किया जाएगा। इस परियोजना को 19 जून 2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी, और इसका निर्माण दो चरणों में किया जाएगा।

स्ट्रेटेजिक रूप से स्थित यह बंदरगाह प्रमुख आंतरिक क्षेत्रों से निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसका ऑल-वेदर डिज़ाइन और गहरा मसौदा (डीप ड्राफ्ट) भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को सागरमाला पहल के तहत सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

**वाढवण** बंदरगाह एक 100% ग्रीन पोर्ट बनने के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी स्थापना से ही सतत विकास और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने पर जोर दे रहा है।

**मीडिया संबंधी पूछताछ के लिए संपर्क करें:**
अंबिका सिंह, उपमहाप्रबंधक (कॉर्पोरेट संचार और प्रशिक्षण), वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड।

**मोबाइल नंबर:** +919920372677

**ईमेल:** ambikasingh@jnport.gov.in

# Press Note on Sand Mining for Deep draft green filed Vadhvan Port for reclamation for creation of offshore land.

**Mumbai, February 28th, 2025:** The Vadhavan Port Project Ltd.(VPPL) is developing deep draft greenfield Vadhvan Port Project in Palghar District. The Port is to be created on reclaimed land of 1448 ha. The reclaimed land will be created in the sea, involving filling of sand of about 200 Million CuM. The sand will be dredged at a place in the sea which is 60 km from site and 50 km off coast of Daman. For the purpose of dredging 10277.1 ha (102.77 Sq.KM) area on the off shore has been reserved by the Ministry of Mines for the said purpose. The detailed study was carried out by IIT Madras by taking actual bore holes at site and the samples collected had been tested. IIT Madras has certified that the said sand is fit for the reclamation purpose. JNPA had made an application to the Ministry of Mines for reservation and reclamation of the sand in Oct 2023. The Ministry of Mines reserved the said area for mining for VPPL on 21.12.2023 vide Govt. Notification. Today i.e. on 28th February 2025 the Ministry of Mines has issued Mining Licence under Offshore Area Mineral (Development & Regulations) Act 2006 for a period of 10 years. The Letter of Intent (LOI) has been handed over by Minister of Mines & Coal Shri G. Kishan Reddy in the presence of Shri Devendra Fadnavis the Hon'ble Chief Minister of Maharashtra to CMD VPPL and Chairman JNPA Shri Unmesh Sharad Wagh, IRS. The Secretary Mines of Govt. of India Shri V. Kantha Rao, IAS and Hon'ble Minister of Mines Govt. of Maharashtra Shri Shambhuraj Desai was also present

The cost of 2000 Million CuM sand from land is Rs.12000 crores which includes Rs.1440 crores as royalty to GOI. But sand from the sea has saved Rs.6000 Crores as against sand and murum used from the land sources. Apart from the savings in cost the mining from the sea has negligible environmental impact compared to the mining on land.

**About VPPL:**

Situated in Palghar district, near Dahanu, Maharashtra, Vadhvan Port is set to become India's 13th major and largest container port. It is being developed under a landlord model with terminals built through Public-Private Partnerships (PPP). The project received cabinet approval on June 19, 2024, with construction in two phases.

Strategically located with seamless connectivity to major hinterlands, the port's all-weather design and deep draft make it crucial for boosting India's maritime economy under the Sagarmala initiative.

Vadhvan Port is committed to being a 100% green port, incorporating sustainable and eco-friendly practices in its operations since its inception.

**For Media Queries, Contact:**

Ambika Singh, DGM (Corporate Communications & Training), Vadhvan Port Project Ltd.
**Mob:** +919920372677
**E-mail:** ambikasingh@jnport.gov.in